सांसदों को वाहन

2639. श्री सलीमुद्दीन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अन्तर्गत सभी सांसद स्कूटर, मोटर-साइकिल, ट्रक तथा डीजल वाहनों के लिये अधिकृत हैं; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इन गाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर नियंत्रण नहीं है और फलस्वरूप सदस सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को इन गाडियों का आवंटन करने के लिए सरकारी कोटा नहीं है ।

D.S.I.D.C., the Principal Employer of Stone Quarries in Delhi

2640. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Delhi State Industrial Development Corporation (DCIDC) is the principal employer of the stone quarries in Delhi (near Mehrauli);

(b) if so, the details;

(c) whether the labourers had struck work for two days in the beginning of June, 1980;

(d) if so, their demands; and

(e) the steps taken to look into the grievances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) and (b). Yes, Sir, By virtue of the application of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Delhi State Industrial Development Corporation took over the stone mining operation in the Union Territory of Delhi.

(c) Yes, Sir. Some workers working in a quarry near village Mandi stopped work for two days.

(d) Their main demands were:—

(i) Increase in stone rate by buyers;

(ii) Improvement of drinking water facilities; and

(iii) Improvement of First Aid facilities.

(e) Increase in stone rate has been mutually settled and implemented,

(ii) Drinking water facilities are being improved; and

(iii) Improvements made in first aid facilities by increasing the visits of medical officer, medicines etc.

राजस्थान प्रशासनिक सेवा का भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये कोटा

2641. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक तिहाई पदोन्नति कोटा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिये नियत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य प्रशासनिक सेवा को उक्त कोटे के अनुसार पदोन्नति के अवसर प्रदान किये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो यह कोटा कब तक पूरा किया जायेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवाओं से 40 प्रतिशत पदोन्नति कोटे की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार यह सिफारिश कब स्वीकार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी ?